

स्थानीय लोगों के लिये नौकरियों की बढ़ती प्रवृत्ति

प्रलिस के लिये:

अनुच्छेद 14, 15, 16 और 19

मेन्स के लिये:

स्थानीय लोगों के लिये नौकरियों के बढ़ते चलन और इससे जुड़ी चिंताएँ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा विधानसभा ने राज्य के 75% नजी क्षेत्र की नौकरियों को स्थानीय नवासियों के लिये आरक्षण करने हेतु **हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार वधियक, 2020 (Haryana State Employment of Local Candidates Bill, 2020)** पारित किया है।

- इसने स्थानीय लोगों के लिये नौकरियों के बढ़ते चलन और इससे जुड़ी चिंताओं पर एक नई बहस छेड़ दी है।

प्रमुख बिंदु

- वधियक के प्रावधान:**
 - प्रत्येक नयिकता ऐसे पदों पर **75% स्थानीय उम्मीदवारों को नयिकत** करेगा जिनका सकल मासिक वेतन या मज़दूरी 50,000 रुपए अथवा सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित वेतन से अधिक न हो।
 - स्थानीय उम्मीदवार राज्य के किसी भी ज़िले से हो सकते हैं, लेकिन नयिकता किसी भी ज़िले के स्थानीय उम्मीदवार के रोजगार को स्थानीय उम्मीदवारों की कुल संख्या के 10% तक सीमित कर सकता है।
 - एक नामित पोर्टल (A Designated Portal) बनाया जाएगा, जिस पर स्थानीय उम्मीदवारों और नयिकता को पंजीकरण करना होगा तथा स्थानीय उम्मीदवार तब तक लाभ प्राप्त करने के लिये पात्र नहीं होंगे जब तक कि वे नामित पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं करते।
- कानून बन जाने के बाद यह राज्य भर में स्थिति कंपनियों, टरस्टों, सीमित देयता भागीदारी फर्मों, साझेदारी फर्मों आदि पर लागू होगा।
- उद्योगों के हित में न होने के कारण इसकी आलोचना की गई है क्योंकि इससे उद्योगों की प्रतस्पर्द्धा प्रभावित होगी और हरियाणा में नविश को नुकसान होगा।

स्थानीय लोगों के लिये नौकरियाँ

- स्थानीय लोगों के लिये नौकरी में आरक्षण:**
 - देशीयतावाद (Nativism), भारत में स्थानीय लोगों की नौकरी की सुरक्षा का मुद्दा हाल ही में बढ़ा है।
 - वभिन्न राज्यों ने **स्थानीय लोगों के आरक्षण (Job Reservation For Locals-JRFL)** के लिये नौकरी में आरक्षण के संबंध में समान कदम उठाए हैं, जिसमें प्रस्तावित आरक्षण 30% से 70-80% अधिक है।
 - यह कदम सरकारी और/या नजी क्षेत्रों पर लागू है।
- हाल के प्रयास:**
 - महाराष्ट्र (वर्ष 1968 और 2008), हिमाचल प्रदेश (वर्ष 2004), ओडिशा (वर्ष 2008), कर्नाटक (वर्ष 2014, 2016 और 2019), आंध्र प्रदेश (वर्ष 2019), , मध्य प्रदेश (वर्ष 2019) जैसे राज्यों में कई दलों (सत्तारूढ़ या वपिक्षी नेताओं) द्वारा भी इस पर विचार किया गया है।
 - हालाँकि इनमें से किसी को भी लागू नहीं किया गया है और यह कार्यान्वयन तंत्र की कमी तथा उद्योगों, नकियों के अनच्छिक दृष्टिकोण के कारण केवल कागज़ों तक ही सीमित रह गया है।
- भारत का संविधान अपने कई प्रावधानों के माध्यम से आवागमन की स्वतंत्रता और इसके परिणामस्वरूप भारत में रोजगार की गारंटी देता है।
 - अनुच्छेद-14** भारत के प्रत्येक व्यक्तिको समानता का अधिकार प्रदान करता है।
 - अनुच्छेद-15** जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के वरिद्ध है।

- अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में जन्म-आधारित भेदभाव नहीं होने की गारंटी देता है।
- अनुच्छेद 19 यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं।
- ऐसे विधानों के पीछे का कारण:
 - **वोट बैंक की राजनीति: अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिकों (Inter-State Migrant Workers)** का वृहत स्तर पर एक ऐसा समूह होता है जो प्रायः अपने मतों का उपयोग नहीं करता। यदि इन श्रमिकों और संभावित प्रवासियों को JRFSL के माध्यम से बनाए रखा जा सकता है तथा नौकरी प्रदान की जा सकती है जिससे चुनावी लाभों की पूर्ति होती है।
 - **आर्थिक सुसती:** स्थानीय बेरोजगारी का मुद्दा प्रासंगिक है क्योंकि सरकारी रोजगार कम होने से बेरोजगारी बढ़ गई है।
 - **बढ़ी हुई आय और प्रतभा:** JRFSL न केवल प्रतभा बल्कि आय को बनाए रखेगा जो अन्यथा 'अन्य क्षेत्रों' में जाएगा।
 - **भूमि अधिग्रहण के लिये पूर्व शर्त:** किसान और ग्रामीण जो कि उद्योगों के लिये भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में अपनी जमीन खो देते हैं, ऐसी पूर्व शर्त रखते हैं जिसमें उद्योगों को स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान करना होता है।
- **प्रभाव:**
 - ऐसे प्रतबंधों वाले राज्य में उद्योगों के अवरोध के कारण रोजगार सृजन कम हो गया। यह वास्तव में लाभान्वित करने की तुलना में मूल निवासियों को अधिक नुकसान पहुँचाएगा।
 - इस तरह के प्रतबंध व्यापार को प्रभावित करके संबंधित राज्य और देश के विकास तथा उसकी संभावनाओं को बाधित कर सकते हैं।
 - श्रम गतिशीलता पर प्रतबंध, विविध प्रकार के श्रम से होने वाले ऐसे लाभ की उपेक्षा करेगा जो भारतीय अर्थव्यवस्था की एक ज़रूरत है।
 - यह आक्रामक क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे सकता है और इस प्रकार भारत की एकता तथा अखंडता के लिये खतरा है।
 - श्रम की कमी के कारण जोखिम में वृद्धि, बेरोजगारी में वृद्धि, बढ़ती मज़दूरी, मुद्रास्फीति और बढ़ती क्षेत्रीय असमानता आदि कुछ इसके अन्य संभावित प्रभाव हो सकते हैं।

आगे की राह

- JRLF का विचार एक देश के भीतर एक अलग देश बनाने या फिर किसी एक क्षेत्र विशेष के भीतर एक अलग क्षेत्र बनाने जैसा है, जो कि पूर्णतः इस संदिग्ध अवधारणा पर आधारित है कि स्थानीय बाज़ार में कौशल की कोई कमी नहीं है।
- इससे बाहर बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका आर्थिक सुधार सुनिश्चित करना और कौशल प्रशिक्षण तथा फोकस किये गए क्षेत्रों में उचित शिक्षा के साथ युवाओं के लिये पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान करना है, ताकि जनता को मुक्त बाज़ार में प्रतस्पर्द्धा करने में सक्षम बनाया जा सके।
- राज्यों को एक ऐसा ढाँचा बनाने की ज़रूरत है, जहाँ काम के लिये सुरक्षित अंतरराज्यीय प्रवास की सुविधा हो और सामाजिक सुरक्षा लाभों की सुगम पहुँच को सक्षम करने के लिये राजकोषीय समन्वय किया जाए। यदि ऐसा किया जाता है तो अंतरराज्यीय प्रवास बढ़ जाएगा और यह क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के अधिक अवसर प्रदान करेगा।

स्रोत: द हिंदू